भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1054
सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

रोजगार की पहल

1054. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सिटी ग्रुप की रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने के लिए संघर्ष करेगी, के आलोक में व्यापक रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार वर्ष 2014-19 के बीच कुल रोजगार सृजन संबंधी आंकड़े को प्रकट करने में विफल रही है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट ,जिसमें दावा किया गया है कि भारत में **83** प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं, पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है**?**

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (ग): सरकार ने सिटीग्रुप की उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि भारत 7% की विकास दर के साथ भी पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए संघर्ष करेगा।

रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण की अवधि हर साल जुलाई से जून होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार है:

वर्ष	डब्ल्यूपीआर (% में)	यूआर (% में)
2017-18	46.8	6.0
2018-19	47.3	5.8
2019-20	50.9	4.8
2020-21	52.6	4.2
2021-22	52.9	4.1
2022-23	56.0	3.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त आँकड़ों यह दर्शाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में डब्ल्यूपीआर यानी रोजगार में वृद्धि की प्रवृत्ति है और बेरोजगारी दर में कमी की प्रवृत्ति है।

इसके साथ-साथ, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैः

वर्ष	बेरोजगारी की दर (%)
2017-18	17.8
2018-19	17.3
2019-20	15.0
2020-21	12.9
2021-22	12.4
2022-23	10.0

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त आँकड़ों से पता चलता है कि देश में युवाओं की बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवीनतम केएलईएमएस डेटा के अनुसार, देश में रोजगार वर्ष 2014-15 में 47.15 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। 2014-15 से 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 17.19 करोड़ है। केएलईएमएस के आंकड़े https://www.rbi.org.in/Scripts/KLEMS.aspx पर उपलब्ध हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के साथ साझेदारी में **मानव विकास संस्थान** (आईएचडी) द्वारा तैयार की गई भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, दो डेटा सेट्स, 2000 और 2012 के लिए रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूएस) और 2018 से 2022 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)पर आधारित है।

"कार्यबल परिवर्तन और रोजगार" पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पीएलएफएस सर्वेक्षण एक अलग नमूना ढांचे पर आधारित हैं और रोजगार पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (कन्नन और खान 2022) की तुलना में एक अलग विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करता हैं। इस वजह से, एनएसएसओ के सर्वेक्षणों से उपलब्ध रोजगार और बेरोजगारी पर समय श्रृंखला डेटा, पीएलएफएस डेटा के साथ तुलनीय नहीं है।

रोजगार सृजन के साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार पैदा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), जैसी रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes कार्यक्रम पर देखा जा सकता है।

*****